ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे : प्रॉपटी डीलर के अवतार में केन्द्रीय मंत्री किशनपाल ने मुनाफाखोरी के लिए फरेंदा पर बनवाया कट

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देने के लिए बनाए जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर नोएडा के करीब, फरेंदा में अरबों रुपये कीमत की करीब सात सौ एकड़ जमीन का सौदा केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर के रिश्तेदारों के नाम हुआ है। रिश्तेदारों को लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने मोहना गांव के लोगों को धोखा देते हुए एक्सप्रेस वे पर फरेंदा में ही कनेक्टिविटी के लिए उतार चढ़ाव कट बनवाया। सत्ता का दुरुपयोग कर अरबों रुपये की संपत्ति बनाने के केंद्रीय मंत्री के इस खेल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का खुला समर्थन मिला। ये आरोप एक्सप्रेस वे पर मोहना गांव में उतार चढ़ाव कट बनवाने के लिए बीते डेढ़ वर्ष से संघर्ष कर रहे ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे मुकेश कुमार ने लगाए।

फरीदाबाद से नोएडा जेवर एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर मोहना गांव में एंट्री एक्जिट प्वाइंट बनाए जाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। मुकेश कुमार के अनुसार 3 मई 2022 को सीएम खट्टर मोहना में एक भंडारे में शामिल होने आए थे। वहां क्षेत्रीय विधायक नैनपाल और ग्रामीणों की मांग पर खट्टर ने मोहना में एंट्री एक्जिट प्वाइंट बनाए जाने की घोषणा की थी। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर ने भी मोहना में ही एंट्री-एक्जिट प्वाइंट बनवाने का वादा किया था। डेढ़ वर्ष में इस मुद्दे पर ग्रामीण किशन पाल गूजर से पचास से अधिक बार मिले।

हार बार गूजर का जवाब होता क्यों पागल हो रखे हो, उतार चढ़ाव बनना है तो बनना है।

मंत्री के आश्वासन पर ग्रामीण निश्चिंत थे। तीन अक्तूबर को किशनपाल के करीबी कुछ भाजपाई मोहना गांव वालों से मिले और बताया कि उतार मोहना में नहीं बल्कि शुरुआत से तीन किलोमीटर बाद सोतई में और अंतिम छोर से पांच किलोमीटर पहले फरेंदा गांव में बन रहा है, साथ में एक्सप्रेस वे के अप्रूव डिजायन की ड्राइंग भी दी। डेढ़ साल बाद धोखा दिए जाने से दुखी ग्रामीण दूसरे ही दिन किशनपाल गूजर से मिले। गूजर ने ग्रामीणों के सामने झूठ दोहराते हुए कहा कि जब कह दिया कि उतार चढ़ाव मोहना में बनेगा तो बनेगा। ग्रामीणों ने ड्राइंग सामने रखी तो गूजर का चेहरा फक्क पड़ गया। बेशर्मी दिखाते हुए बोला कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो कहां कट बनवाना है कहां नहीं बनवाना, मैने ही स्टार्टिंग प्वाइंट से तीन किलोमीटर बाद और एंड प्वाइंट से पांच किलोमीटर पहले कट बनवाएं है, मैं हर गांव पर कट नहीं बनवा सकता। ग्रामीणों ने उनसे दोबारा सोच विचार करने की मिन्नत की तो धमकी भरे अंदाज में जवाब दिया कि न मैं तो लिख कर दे सकता हूं न शपथ पत्र दे सकता हूं मुझसे वकीलों वाली बात मत करो, मैं तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा करने का प्रयास करूंगा। ग्रामीणों ने उन्हें चुनाव जिताने में की गई मेहनत का वास्ता दिया तो बोले कि तुमने मुझे वोट थोड़ी दिया था तुमने तो मोदी को वोट दिया था। मंत्री के दुर्व्यवहार से अपमानित आस पास के एक दर्जन से अधिक गांव की सरदारी ने मोहना में कट बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।

भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार गूजर ने फरेंदा और सोतई में इसलिए कनेक्टिविटी दिलाई कि वहां की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद कर प्लॉटिंग कर अरबों रुपयों का वारा न्यारा किया जा सके। किशन पाल के रिश्तेदारों के नाम करीब सात सौ एकड़ जमीन फरेंदा में खरीदी भी जा चुकी है। सत्ता के दम पर जमीन का काला कारोबार किशनपाल के लिए उसका करीबी महमदपुर निवासी सतवीर कसाना कर रहा है। यह वही सतवीर कसाना है जिसका नाम पुलिस दलालों की सूची में किशन पाल के मामा राजपाल, भांजे अमर चेची के साथ शामिल था। ग्रामीणों के अनुसार सात सौ एकड़ तो गूजर के रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई है जबकि बहुत सारी जमीन बेनामी रूप से भी खरीदी गई है। यही कारण है कि गूजर ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए फरेंदा में ही कनेक्टिविटी दिलवाई। सोतई में भी जमीन खरीदी का खेल शुरू हो गया होगा भविष्य में इसका भी खुलासा हो सकता है।

नोएडा के करीब होने के कारण कनेक्टिविटी मिलते ही फरेंदा में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़नी शुरू हो गई हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहां का सर्किल रेट 20-25 लाख रुपये एकड़ के आसपास है, बावजूद इसके यहां कोई बीस लाख रुपये की दर से भी जमीन नहीं खरीदता था। एक माह पहले एक एकड़ के लिए 4.13 करोड़ रुपयों में एग्रीमेंट हुआ है। एक्सप्रेस वे तैयार होने और कनेक्टिविटी मिलते ही यहां जमीन की कीमत दस करोड़ रुपये एकड़ तक पहुंच जाएगी। अंदाज लगाया जा सकता है कि कौड़ियों के दाम खरीदी गई सात सौ एकड़ जमीन महज डेढ़ दो साल के बाद अरबों रुपये की हो जाएगी।

डूब क्षेत्र में आता है फरेंदा

मुकेश कुमार के अनुसार मोहना ही एंट्री-एक्जिट प्वाइंट के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी क्योंकि फरेंदा डूब क्षेत्र में आता है। प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए कहते हैं वहां एक्सप्रेस वे को पिलर से गुजारना चाहिए क्योंकि यमुना में बाढ़ आने पर वह इलाका डूब जाता है, बावजूद इसके यहां मिट्टी का भरत करके सड़क बनाई जा रही है। बूढ़ी यमुना में बाढ़ आने पर वहां करीब पंद्रह फीट तक जलभराव हो जाता है। मोहना जाने के लिए रबड़ फैक्ट्री की ओर जाने वाले रास्ते को पांच वर्ष पहले मिट्टी भरत करके पांच फुट ऊंची सड़क बनाई गई थी। बाढ़ आने पर इस सड़क ने बांध की तरह पानी को रोका था, इसका नतीजा यह हुआ कि पानी कई जगहों पर सड़क को बहा ले गया और छोटी मोटी पुलिया भी तोड़ डाली थीं। फरेंदा में तो बाढ़ में पंद्रह फीट ऊंचाई तक जलभराव होता है, यहां मिट्टी भरत कर बनाया जा रहा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बाढ़ में तबाह हो जाएगा, बेहतर होता कि यहां पिलर पर हाईवे गुजारा जाता। लेकिन गूजर को तो यहां की जमीन से अरबों रुपये कमाने हैं इसलिए सड़क भी बनाई जा रही है और कनेक्टिविटी भी दी जा रही है।

सीएम बोले जमीन की कीमत बढ़ रही है तो तुम भी खरीद लो

ईमादारी का ढिंढोरा पीटने वाले सीएम खट्टर को भी केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर की इस बेईमानी का खुल कर समर्थन प्राप्त है। ग्रीवांस कमेटी की बैठक में शामिल होने आए खट्टर से बैठक के बाद मोहना गांव की सरदारी मिली थी। इन लोगों ने खट्टर से गूजर का नाम लिए बिना शिकायत की थी कि कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कट फरेंदा लेकर गए हैं। वहां कट बनने से जमीन के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं तो सीएम ने सहजता से जवाब दिया था कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता तुम लोग भी वहां जमीन खरीद लो। ईमानदारी का लबादा ओढ़ने वाले खट्टर को ग्रामीणों की शिकायत पर तुरंत अपनी घोषणा वाले मोहना गांव में कट बनवाने का आदेश देना चाहिए था लेकिन संघ से शिक्षा पाए खट्टर खुलेआम आरोपी का पक्ष लेकर ग्रामीणों को धता बताते हुए चले गए।

विकसित भारत संकल्प यात्रा : पार्टी कार्यकर्ता तो भाग गए, अब अफसर पीटेंगे सरकारी ढिंढोरा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। भाजपा का विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के भरोसे रहने के बजाय विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम पर प्रशासन को अपनी सरकार का प्रचार प्रसार करने में झोंक रहे हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी अब सरकारी काम-काज छोड़ कर तीन महीने तक सरकार की उपलब्धियों का झंडा उठा कर शहर-शहर, गांव-गांव घूमेंगे। इन अधिकारियों का दफ्तर छोड़ कर गैर सरकारी काम में लगने का खामियाजा आम जनता को सरकारी कार्यालयों से बिना काम ही लौटने के रूप में भुगतना पड़ेगा, छात्रों की पढ़ाई भी चौपट होगी।

दो करोड़ रोजगार, आम जनता के खाते में पंद्रह लाख रुपये आने का झूठ बोल कर सत्ता हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने प्रचार एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। फरीदाबाद में सरकार का ढिंढोरा पीटने का जिम्मा केन्द्र सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के निदेशक महेन्द्र कुमार को नोडल अधिकारी बनाकर सौंपा गया है। वो अब 22 नवंबर से 21 जनवरी-2024 तक अपने सारे काम काज छोड़ कर प्रतिदिन विकसित भारत संकल्प यात्रा की निगरानी करेंगे। किसी तरह की समस्या आने पर उसे दूर करेंगे और जिला स्तर के अधिकारियों को इस यात्रा में शामिल होकर जनता से संपर्क करने की समीक्षा करेंगे। अच्छा काम करने वाले और हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजेंगे, ताकि जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी यात्रा को प्राथमिकता से पूरे जोर शोर से सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ें।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अप्रत्यक्ष कर का बोझ आदि ज्वलंत समस्याओं के कारण भाजपा का जनाधार बहुत तेजी से घटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़बोली घोषणाओं का झूठ सामने आने से आम जनता खासकर मध्यम वर्ग का मोहभंग हो चुका है। मणिपुर हिंसा को संभालने के बजाय चुनावी रैलियों को प्राथमिकता दिए जाने से भी आम जनता में नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हुई। राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का जादू नहीं चल सका। 2024 मार्च-अप्रैल में लोकसभा चुनाव शुरू होने हैं ऐसे में प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मोहभंग होने के कारण मैदान छोड़ कर भाग चुके हैं ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी सरकार का ढिंढोरा पीटने के लिए लगाया जा रहा है।

बुजुर्ग समाजसेवी सुरेश गोयल कहते हैं कि आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार आला प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। सवाल करते हैं कि तीन महीने के कार्यक्रम, कैंप, यात्रा आदि का खर्च कहां से किया जाएगा ? यदि यह सरकारी कार्यक्रम है तो इसके लिए कितने बजट का प्रावधान है, यदि बजट का प्रावधान नहीं है तो किस मद से खर्च किया जाएगा। बिना बजट के तीन महीने का कार्यक्रम कैसे से किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां तो इस तरह की यात्राएं अपने खर्च पर निकालती हैं, यदि सरकार ने इस यात्रा के लिए बजट अलॉट नहीं किया तो जाहिर है कि कल्याणकारी योजनाओं या विकास कार्यों का धन इसमें लगाया जाएगा जो कि नियमानुसार अनुचित है।

सरकारी नमक यानी वेतन खा रहे ये आला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी जनता के सामने केवल सरकार का उजला पक्ष दिखाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, खराब स्वास्थ्य सेवाओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों को अनदेखी की चादर से ढंक दिया जाएगा। यदि इस दौरान चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी भी कर देता है तो प्रशासनिक होने के कारण विकसित भारत संकल्प यात्रा पर रोक नहीं लगाई जाएगी और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी-खट्टर सरकार का प्रचार होगा।

आईआरएस महेंद्र कुमार के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर स्कूलों में भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। यानी छात्रों की पढ़ाई भी चौपट करने का भी इंतजाम है।

फरवरी, मार्च में होने वाली विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों के पास करीब तीन महीने का समय है लेकिन सरकार की खुशी के लिए अधिकारी उन्हें बोर्ड परीक्षा की नहीं बल्कि प्रतियोगिता की तैयारी करवाएंगे, जिनमें सरकार की योजनाओं के बारे में सवाल पूछे जाएंगे।